



नए सिरे से ध्यान

भारत और जापान ने दिखाया कि वैश्विक उथल-पुथल के बीच उनके संबंध स्थिर हैं।

अपने पूर्वी दौरे के पहले चरण में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए तियानजिन जाने से पहले जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए दो दिवसीय जापान यात्रा की। भारत में पिछला शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ था। दोनों पक्षों ने कम से कम एक दर्जन दस्तावेज़ जारी किए, जिनका मुख्य उद्देश्य अपने समझौतों को अद्यतन करना और उन्हें "अगली पीढ़ी" पर केंद्रित करना था। जापानी व्यवसायों ने भारत में अपने निवेश लक्ष्य को बढ़ाकर 68 अरब डॉलर कर दिया है और भारतीय भागीदारों के साथ लगभग 170 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त वक्तव्य के अलावा, 2035 का एक विज्ञान वक्तव्य भी था, जिसमें आर्थिक सुरक्षा, गतिशीलता और हरित प्रौद्योगिकी परिवहन जैसे सहयोग के आठ क्षेत्र शामिल थे। "अगली पीढ़ी की राज्य-प्रान्त साझेदारी" ने जमीनी स्तर के संबंधों और सीधी उड़ान कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर प्रकाश डाला। भारत और जापान ने अपनी 2008 की सुरक्षा साझेदारी को अद्यतन करते हुए इसमें वार्षिक एनएसए-स्तरीय वार्ता, क्वाड पर अधिक जुड़ाव, हिंद-प्रशांत सहयोग और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार शामिल किए। दिलचस्प बात यह है कि उनका आर्थिक सुरक्षा साझेदारी लक्ष्य लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण और महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को सुरक्षित करना है, जिसके तहत जापानी तकनीक का उपयोग करके भारत में सेमीकंडक्टर तकनीक के निर्माण और प्रसंस्करण में मदद की जाएगी, क्योंकि भारतीय कंपनियों को दुर्लभ पृथ्वी चुम्बकों के निर्यात पर चीनी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। भारत की हाई स्पीड रेल "बुलेट ट्रेन" परियोजना के साथ जापान के सहयोग का प्रदर्शन किया गया, जिसमें श्री मोदी और श्री इशिबा ट्रेन से मियागी प्रांत गए, जहाँ उन्होंने एक सेमीकंडक्टर कारखाने का भी निरीक्षण किया। संयुक्त बयान में उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों और परमाणु कार्यक्रम, और पहलगाम हमले और सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई, हालाँकि पाकिस्तान का उल्लेख नहीं किया गया। नेताओं ने इस वर्ष भारत में नेताओं के आगामी क्वाड शिखर सम्मेलन के महत्व पर भी जोर दिया, जो भारत के खिलाफ श्री ट्रम्प की कार्रवाइयों के कारण संदेह के घेरे में आ गया है।

यद्यपि भारत-जापान बैठकों का मूल पाठ काफी हद तक द्विपक्षीय था, लेकिन इसका निहितार्थ भू-राजनीतिक था। श्री मोदी भारी अमेरिकी टैरिफ के मद्देनजर टोक्यो गए, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के बिगड़ने का खतरा है। उन्होंने रविवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ चार साल के गतिरोध के बाद संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में अपनी वार्ता से पहले जापान को अपना पहला पड़ाव चुना। जापान भी पूर्वी चीन सागर की स्थिति को लेकर चिंतित है और अमेरिका के साथ व्यापार को लेकर उसका तनाव है, जिसके कारण उसने वाशिंगटन में व्यापार वार्ता दल का दौरा रह कर दिया। श्री मोदी और श्री इशिबा ने जो संदेश दिया वह यह था कि वैश्विक शक्तियों द्वारा उत्पन्न भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच, भारत-जापान संबंध स्थिर बने हुए हैं और निरंतर विकसित हो रहे हैं।

आवर्ती उत्तेजक

धन और वेतन के वितरण में देरी से अनुसंधान परियोजनाएं पटरी से उतर सकती हैं

विज्ञान में समय का बहुत महत्व है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के बायोकेयर कार्यक्रम के लिए चुनी गई 75 महिलाओं को न तो स्वीकृति पत्र मिले हैं और न ही वेतन, यह रिपोर्ट भारत के अनुसंधान प्रशासन की एक कष्टप्रद और निरंतर दुर्बलता की याद दिलाती है। युवा शोधकर्ता पहले से ही प्रयोगशालाओं की कमी, बोझिल विश्वविद्यालय नौकरशाही, जटिल अनुदान आवेदनों, असमान मार्गदर्शन और अनिश्चित करियर संभावनाओं से जूझ रहे हैं। वेतन और फेलोशिप जीवन-यापन की लागत के मुकाबले मामूली हैं, जो प्रतिभाशाली स्नातकों को शोध करने से रोकता है। यहाँ तक कि जो रुकने के लिए दृढ़ हैं, वे भी अक्सर दीर्घकालिक सुरक्षा के बिना लंबी अवधि की पोस्टडॉक्टरल या संविदात्मक भूमिकाओं में फँस जाते हैं। इस परिवेश में, बायोकेयर जैसी योजना एक स्वतंत्र आधार का वादा करती है, जबकि समय पर इसके पूरा न होने से असुरक्षा और हतोत्साह बढ़ता है। विदेशों में पोस्टडॉक्टरल कार्य और टेन्पोर-ट्रैक नौकरियों के अवसर भी कम हो रहे हैं। पश्चिम में आरजन व्यवस्थाएँ कड़ी हो गई हैं, जबकि सीमित संकाय पदों के लिए प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। इस प्रकार, भारतीय वैज्ञानिकों के लिए, घरेलू अनुसंधान परिस्थितिकी तंत्र तेजी से वह क्षेत्र बनता जा रहा है जहाँ उनके करियर का विकास होगा। फेलोशिप और अनुदान विभागों में देरी पूरे करियर को पटरी से उतार सकती है।

भारत अब इस तरह की कमियों को शुरुआती मुश्किलों की तरह नहीं देख सकता। देश अपनी वैश्विक वैज्ञानिक स्थिति का विस्तार करना चाहता है, अनुसंधान को नवाचार में बदलना चाहता है, और स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में गंभीर चुनौतियों का समाधान करने के लिए वैज्ञानिकों की एक पीढ़ी को प्रशिक्षित करना चाहता है। ये महत्वाकांक्षायें उस वित्त पोषण प्रशासन के साथ असंगत हैं जो बुनियादी क्रियान्वयन में लड़खड़ाता है। बायोकेयर में देरी का कथित कारण, ट्रेजरी सिंगल अकाउंट सिस्टम में बदलाव, लंबे समय में पारदर्शिता को मजबूत कर सकता है, लेकिन अभी प्रशासनिक परिपक्वता की तत्काल आवश्यकता के कई कारण हैं। सबसे पहले, विज्ञान समय के प्रति संवेदनशील है: प्रयोग तब शुरू होने चाहिए जब सुविधाएँ, सहयोगी और मौसमी या जैविक परिस्थितियाँ एक-दूसरे के अनुकूल हों। देरी इन चक्रों को अपरिवर्तनीय रूप से तोड़ देती है। दूसरा, जब कागज पर प्रगतिशील योजनाएँ लाभार्थियों तक पहुँचने में विफल रहती हैं, तो परिणामस्वरूप विश्वसनीयता की कमी घरेलू प्रतिभा और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को आकर्षित करना कठिन बना देगी। तीसरा, समानता निरंतरता की माँग करती है। महिला वैज्ञानिक, शुरुआती करियर वाले फेलो और कम प्रतिनिधित्व वाली पृष्ठभूमि से आने वाले लोग पहले से ही प्रणालीगत बाधाओं से जूझ रहे हैं। निधियों तक अनियमित पहुँच उन्हें असमान रूप से प्रभावित करती है। योजना के डिजाइन में प्रवर्तन को बाहरी बनाने के बजाय उसे शामिल किया जाना चाहिए। पारदर्शिता को आकस्मिकताओं के साथ लागू किया जाना चाहिए ताकि लाभार्थी नौकरशाही परिवर्तनों में अतिरिक्त क्षति का शिकार न बनें। मंत्रालयों और कार्यक्रम प्रबंधकों के स्तर पर जवाबदेही कड़ी की जानी चाहिए। नीति निर्माताओं को यह समझना होगा कि उनके लिए लेखांकन प्रक्रियाओं में देरी शोधकर्ताओं की आजीविका और करियर में बाधा है।

भारतीय सभ्यता लंबे समय से मानती रही है कि विजय से पहले परीक्षाएँ आती हैं। समुद्र मंथन की तरह, जहाँ उथल-पुथल से अमृत निकला, हमारे आर्थिक मंथन ने हमेशा नवीनीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। 1991 के संकट से उदारीकरण आया और कोविड-19 महामारी से डिजिटल उछाल आया। और, आज, भारत को "मृत अर्थव्यवस्था" कहने वाले संदेहियों के शोरगुल से लचीलेपन की तथ्य-समृद्ध कहानी उभर रही है: तेज विकास, मजबूत बफर्स और व्यापक अवसर।

आर्थिक आँकड़े-ऊर्जा सुरक्षा संबंध

जीडीपी के नवीनतम आँकड़ों पर विचार करें। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी 7.8% बढ़ी, जो पाँच तिमाहियों का उच्चतम स्तर है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वृद्धि व्यापक है: सकल मूल्य वर्धन 7.6% बढ़ा है, जिसमें विनिर्माण 7.7%, निर्माण 7.6% और सेवाएँ लगभग 9.3% बढ़ी हैं। नाममात्र जीडीपी में 8.8% की वृद्धि हुई है। यह कोई मनमाना उछाल नहीं है - यह बढ़ती खपत, मजबूत निवेश और स्थिर सार्वजनिक पूंजीगत व्यय तथा लॉजिस्टिक्स सुधारों से होने वाले लाभ को दर्शाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में लागत कम होती है।

भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जो पहली और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से भी आगे निकल गई है। वर्तमान गति के अनुसार, भारत इस दशक के अंत से पहले जर्मनी को पीछे छोड़कर बाज़ार विनिमय के संदर्भ में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। भारत की गति वैश्विक स्तर पर मान्ये रखती है; स्वतंत्र अनुमान बताते हैं कि भारत पहले से ही वैश्विक वृद्धि में 15% से अधिक का योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री ने एक स्पष्ट महत्वाकांक्षा रखी है - जैसे-जैसे सुधार गहराते हैं और नई क्षमताएँ सामने आती हैं, भारत की हिस्सेदारी 20% तक बढ़ना।।

बाजारों और रेटिंग एजेंसियों ने इस अनुशासन को मान्यता दी है। एसएंडपी ग्लोबल ने मजबूत विकास, मौद्रिक विश्वसनीयता और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का हवाला देते हुए, 18 वर्षों में भारत की पहली साँवरेन रेटिंग में सुधार किया है। इस सुधार से उभार लेने की लागत कम होती है और निवेशक आधार का विस्तार होता है। यह "मृत अर्थव्यवस्था" की धारणा को भी तोड़ता है: जोखिम के स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं ने अपनी रेटिंग के साथ मतदान किया है।

यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इसका लाभ किसे मिलता है। 2013-14 और 2022-23 के बीच, 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। यह बदलाव बुनियादी सेवाओं की बड़े पैमाने पर आपूर्ति पर निर्भर करता है - बैंक खाते, स्वच्छ रसोई ईंधन, स्वास्थ्य बीमा, नल का जल - और प्रत्यक्ष हस्तांतरण जो गरीबों को चुनाव करने का अधिकार देते हैं। दुनिया के सबसे जीवंत लोकतंत्र और उल्लेखनीय जनसांख्यिकीय चुनौतियों के बीच विकास का यह स्तर विशिष्ट है। भारत का मॉडल आम सहमति बनाने, प्रतिस्पर्धी संघवाद और डिजिटल रेल के माध्यम से अंतिम छोर तक सेवा प्रदान करने को महत्व देता है। इसकी घोषणा धीमी, कार्यान्वयन तेज और टिकाऊ है। जब आलोचक हमारी तुलना सत्तावादी स्पिटेर्स से करते हैं, तो वे इस बात को नज़रअंदाज़ कर देते हैं: भारत एक मैराथन धावक की अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहा है।

भारत के पेट्रोलियम मंत्री के रूप में, यह लेखक इस बात की पुष्टि कर सकता है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा इस तीव्र विकास का समर्थन कैसे करती है। आज, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता, चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और चौथा सबसे बड़ा तरलईकृत प्राकृतिक गैस आयातक है।

15 अगस्त, 2025 को अलास्का शिखर सम्मेलन का नतीजा डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन, या संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, या अमेरिका और यूरोप के बीच किसी कूटनीतिक मुकाबले का नतीजा नहीं था। न ही यह श्री ट्रंप द्वारा यूरोपीय नेताओं और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ हुई बातचीत का नतीजा था। शांति के सवाल को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा अज्ञात कारक यह था कि श्री ट्रंप रूस को कितना मानेंगे। हालाँकि उन्होंने स्थायी शांति समझौते के बिना युद्धविराम न करने और यूक्रेन में उत्तरी अटलॉंटिक संधि संगठन (NAT) न बनाने की श्री पुतिन की माँग मान ली, लेकिन 2024 में श्री ट्रंप के चुनावी मंच ने इससे कहीं ज़्यादा का वादा किया था - युद्ध की तत्काल समाप्ति।

श्री ट्रंप मास्को को उसकी प्रगति रोकने के बदले में आवश्यक प्रोत्साहन देकर और हथियारों की आपूर्ति तथा खुफिया जानकारी साझा करके कीव को समझाने के ज़रिए ऐसा कर सकते थे और अपने समर्थकों को संतुष्ट कर सकते थे। शांति स्थापित करने में उनकी असमर्थता, उस मंच को लागू करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्ति की सीमाओं को उजागर करती है जिस पर उन्हें लोकतांत्रिक रूप से चुना गया था।

ये सीमाएँ अमेरिका के अंदर चल रहे एक संघर्ष के कारण हैं—ऐसा संघर्ष जो किसी भी देश के आंतरिक सत्ता संघर्ष से कहीं ज़्यादा भविष्य की वैश्विक सुरक्षा को आकार देगा। इसमें भारत के अमेरिका की प्रतिक्रियाओं को आकार देना भी शामिल है। यह अमेरिका-प्रथम या हस्तक्षेप-विरोधी खेमे और उन लोगों के बीच संघर्ष है जिनका प्रतिनिधित्व श्री ट्रम्प स्वयं सत्ता में आने के बाद करते हैं—स्थायी वाशिंगटन।

2024 से आगे

2024 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान, श्री ट्रम्प ने वादा किया था कि वह यूक्रेन युद्ध को 'कार्यभार ग्रहण करने के पहले दिन' और 'कार्यभार ग्रहण करने से पहले' समाप्त कर देंगे। यह आश्चर्यजनक था। चुनावी वादे आमतर पर लोकप्रिय माने जाने वाले वादे होते हैं, और पश्चिमी मुख्यधारा के मीडिया ने रूस के साथ शांति के किसी भी आह्वान को कलंकित करते हुए दो साल बिताए थे, इसे एक मामूली राय के रूप में खिंच दिया था। लेकिन श्री ट्रम्प जानते थे कि वह बात शायद ही कभी उजागर हुई—कि अमेरिकी जनता सहमत थी। क्विंसी इंस्टीट्यूट के सर्वेक्षण में पाया गया कि 2024 के आरंभ में भी 66% अमेरिकी लोग युद्ध को बातचीत के माध्यम से समाप्त करने का समर्थन करते हैं, भले ही इसमें रूस के साथ समझौता करना पड़े।



Hardeep S. Puri

is Union Minister for Petroleum and Natural Gas, Government of India

भारत की लचीलेपन, विकास और ऊर्जा सुरक्षा की तथ्य-समृद्ध कहानी उन 'वैश्विक संदेहियों' को चुप करा देगी जो इसे 'मृत अर्थव्यवस्था' कहते हैं।

यूक्रेन अमेरिका और वाशिंगटन के बीच एक लड़ाई है



Kadira Pethiyagoda

is an author, adviser and geopolitical strategist

यह अमेरिकी जनता के बीच बढ़ते और व्यापक रूप से स्वीकृत रुख को दर्शाता है कि अमेरिका को अपने विश्वव्यापी सैन्य अभियानों को कम करना चाहिए और संसाधनों का घरेलू स्तर पर पुनर्वितरण करना चाहिए। पिछले आठ अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में से छह में ऐसे उम्मीदवार जीते हैं जो अपने प्रतिद्वंद्वी की तुलना में कम हस्तक्षेपकारी विदेश नीति चाहते थे।

यह हस्तक्षेप-विरोधी रुख भारत, चीन और रूस जैसी अन्य महाशक्तियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभुत्व बनाए रखने के प्रति आशावादी है, जबकि अमेरिका अपने ही गोलार्ध को प्राथमिकता देता है।

ट्रम्प का दृष्टिकोण बनाम कारक

हस्तक्षेप-विरोधी भावना श्री ट्रम्प के 'अमेरिका को फिर से महान बनाओ' (MAGA) आंदोलन का केंद्रबिंदु है और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस और भारतीय-अमेरिकी रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी जैसे सच्चे विश्वासियों द्वारा इसका समर्थन किया जाता है। श्री ट्रम्प की चुनावी जीत शांति का एक लोकप्रिय समर्थन थी, खासकर यह देखते हुए कि यह विदेश नीति का एकमात्र ऐसा पहलू था जहाँ (पूर्व) अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की विदेश नीति से एक सार्थक, स्पष्ट अंतर था।

इस स्पष्ट जनादेश और रूस की स्पष्ट, दीर्घकालिक माँगों को देखते हुए शांति के सीधे रास्ते के बावजूद, चुनाव के बाद से श्री ट्रम्प का दृष्टिकोण ढ़लभुल रहा है। जहाँ तक दिखावे और सार्वजनिक आख्यान की बात है, उन्होंने अपने वादों के अनुरूप कुछ प्रगति की है। उन्होंने यूक्रेन के देवत्व (व्हाइट हाउस में श्री जैलेन्स्की को फ्टकर लगाकर) और रूस के दानवीकरण (अलास्का शिखर सम्मेलन) दोनों को कमज़ोर किया। ऐसा करके, उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ अमेरिकी कूटनीति को फिर् से सामान्य बनाने में मदद की है, जो एक अधिक व्यावहारिक समय की ओर इशारा करता है।

हालाँकि, शांति की दिशा में श्री ट्रम्प की ठोस नीतिगत कार्रवाई, उनके वादों का एक अंश मात्र है। ज़्यादा से ज़्यादा, उन्होंने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति और उसके साथ खुफिया जानकारी साझा करने पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी। लेकिन कीव के बचाव के लिए लगातार धन मुहैया कराने और रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर लगाए गए द्वितीयक प्रतिबंधों जैसे बढ़ते कदमों ने इसे कमज़ोर कर दिया। हाल ही में, श्री ट्रम्प ने यूक्रेन के लिए 'युद्धोत्तर सुरक्षा गारंटी' के असफल प्रस्ताव के समर्थकों को खुश किया।

इस दुविधा का कारण श्री ट्रम्प और उनके आंदोलन, और राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी की मृत्यु के बाद से अमेरिकी विदेश नीति पर बड़े पैमाने पर हावी रहे लोगों के बीच एक प्रतिस्पर्धा, एक सतत बातचीत, एक आगे-पीछे की स्थिति है। आइजनहावर द्वारा संक्षेप में रेखांकित किया गया उत्तरार्द्ध, वाणिज्यिक और वैचारिक हितों के एक गठबंधन से बना है, जो अपनी प्राथमिकताओं में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं: मुख्यतः निरंतर सैन्य कार्रवाई और खर्च के लिए, और गौण रूप से अमेरिकी वैश्विक आधिपत्य के लिए। इसका प्रतिनिधित्व 'स्थायी वाशिंगटन' द्वारा किया जाता है: 'नव-रूढ़िवादी' राजनेता जिन्हें वह धन देता है, और वैचारिक लोक सेवक, जिनमें वे भी शामिल हैं जिन्हें रिपब्लिकन प्रतिष्ठान ने ट्रम्प प्रशासन पर थोपा था। अक्सर यह प्रतिस्पर्धा आंतरिक रूप से व्यक्तियों के भीतर, कभी-कभी स्वयं श्री ट्रम्प के भीतर भी होती है।

टकराव

अलास्का शिखर सम्मेलन इसका एक उदाहरण है। अमेरिकी विदेश नीति के भीतर दो ताकतें आपस में टकरा गई, जिससे एक समझौतावादी परिणाम सामने आया। श्री ट्रम्प को उनकी मनचाही सफलता मिली, श्री पुतिन के लिए लाल कालीन बिछाकर शीत युद्ध काल के भव्य शिखर सम्मेलनों की याद दिलाई, अमेरिकी राष्ट्रपति को एक शांतिदूत-राजनेता के रूप में स्थापित किया और अमेरिकी जनता से किए अपने वादे पर कायम रहे। हालाँकि, रूस को रियायतें दिए बिना, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि युद्ध जारी रहेगा और 'स्थायी वाशिंगटन' के हितों की पूर्ति होती रहेगी।

यूक्रेन युद्ध दुनिया के लिए वैश्विक परमाणु युद्ध के सबसे करीब है। इस रसातल से निकलने का रास्ता जटिल अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं से नहीं है। अमेरिका के भीतर जटिल घरेलू सत्ता संघर्ष चल रहे हैं। अंतिम समाधान अमेरिका बनाम रूस नहीं, बल्कि अमेरिका बनाम वाशिंगटन द्वारा तय किया जाएगा। आने वाले दशकों में कई भू-रणनीतिक प्रतियोगिताएँ भी इसी तरह होंगी।

भारत प्रतिदिन 5.2 मिलियन बैरल से अधिक शोधन क्षमता का संचालन करता है, और इस दशक के अंत तक इसे 400 मिलियन टन प्रति वर्ष से अधिक तक विस्तारित करने का एक स्पष्ट रोडमैप तैयार है।

भारत की ऊर्जा मांग, जिसके 2047 तक दोगुना होने का अनुमान है, वैश्विक मांग में लगभग एक-चौथाई की वृद्धि करेगी, जिससे भारत की सफलता वैश्विक ऊर्जा स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बन जाएगी। सरकार का दृष्टिकोण सुरक्षा को सुधार के साथ जोड़ने का रहा है। अन्वेषण क्षेत्र 2021 में तलछटी बेसिनों के 8% से बढ़कर 2025 में 16% से अधिक हो गया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक दस लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करना है। तथाकथित 'नो-गो' क्षेत्रों में 99% की भारी कमी ने अपार संभावनाओं को जन्म दिया है, जबकि ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (OALP) पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया सुनिश्चित करती है। नए गैस मूल्य निर्धारण सुधारों ने कीमतों को भारतीय कच्चे तेल की टोकरी से जोड़ा है और गहरे पानी और नए कुओं के लिए 20% प्रीमियम की पेशकश की है, जिससे निवेश को बढ़ावा मिला है।

ऊर्जा परिवर्तन की कहानी

भारत की ऊर्जा कहानी केवल हाइड्रोकार्बन की नहीं है; यह परिवर्तन की भी कहानी है। इथेनॉल मिश्रण 2014 के 1.5% से बढ़कर आज 20% हो गया है, जिससे ₹1.25 लाख करोड़ से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और किसानों को सीधे ₹1 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान हुआ है। किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प के तहत 300 से अधिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनका लक्ष्य 2028 तक 5% मिश्रण अधिदेश प्राप्त करना है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियाँ (PSU) हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका रही रही है।

भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद को लेकर कुछ क्षेत्रों में काफी चर्चा हुई है। आइए तथ्यों को शोर से अलग करें। रूसी तेल पर ईरानी या वेनेजुएला के कच्चे तेल की तरह कभी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है; यह G-7/यूरोपीय संघ की मूल्य सीमा प्रणाली के अंतर्गत है, जिसे जानबूझकर राजस्व को सीमित रखते हुए तेल का प्रवाह बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे पैकेजों के 18 दौर हो चुके हैं, और भारत ने प्रत्येक का अनुपालन किया है। हर लेन-देन में कानूनी शिपिंग और बीमा, अनुपालन करने वाले व्यापारियों और ऑडिट किए गए चैनलों का इस्तेमाल किया गया है। भारत ने नियम नहीं तोड़े हैं। भारत ने बाजारों को स्थिर रखा है और वैश्विक कीमतों को बढ़ने से रोका है।

कुछ आलोचकों का आरोप है कि भारत रूसी तेल के लिए एक "धोबीघर" बन गया है। सच्चाई इससे ज़्यादा दूर नहीं हो सकती। भारत दशकों से - यूक्रेन संघर्ष से बहुत पहले से - पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक रहा है और इसके रिफाइनर दुनिया भर से कच्चे तेल की एक टोकरी को प्रोसेस करते हैं। निर्यात आपूर्ति श्रृंखलाओं को चालू रखता है। वास्तव में, रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगाने के बाद यूरोप ने खुद भारतीय ईंधनों की ओर रुख किया। निर्यात और रिफाइनिंग मार्जिन - सकल रिफाइनिंग मार्जिन या जीआरएम - की मात्रा मोटे तौर पर समान बनी हुई है। मुनाफाखोरी का कोई सवाल ही नहीं है।

समान रूप से महत्वपूर्ण, भारत ने यूक्रेन संघर्ष के बाद वैश्विक कीमतों में उछाल के दौरान अपने नागरिकों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाए। तेल सार्वजनिक उपक्रमों ने डीज़ल पर ₹10 प्रति लीटर तक के नुकसान को सहन किया; सरकार ने केंद्रीय और राज्य करों में कटौती की और निर्यात नियमों के तहत विदेशों में पेट्रोल और डीज़ल बेचने वाली रिफाइनरियों को घरेलू बाज़ार में कम से कम 50% पेट्रोल और 30% डीज़ल बेचना अनिवार्य कर दिया।

काफी राजकोषीय लागत पर इन उपायों ने यह सुनिश्चित किया कि एक भी खुदरा दुकान खाली न रहे और भारतीय घरों में कीमतें स्थिर रहें। बड़ा सच यह है कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक, जो वैश्विक तेल का लगभग 10% आपूर्ति करता है, का कोई विकल्प नहीं है। जो लोग उँगली उठा रहे हैं, वे इस तथ्य की अनदेखी करते हैं। भारत द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन करने से 200 डॉलर प्रति बैरल के विनाशकारी झटके को रोका जा सका, जो वसुधैव कुटुम्बकम के उसके सभ्यतागत मूल्यों के अनुरूप है।

यह वही 'मेड इन इंडिया' है जो विश्व दृष्टिकोण के लिए है जो भारत में आकार ले रही नई औद्योगिक क्रांति को आकार देता है। इसमें सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और विशेष रसायन शामिल हैं, जो उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों और प्रधानमंत्री गति शक्ति लॉजिस्टिक्स योजना द्वारा समर्थित हैं। सेमीकंडक्टर में गति अब एक नए स्तर पर पहुँच रही है - जो नीतिगत गंभीरता और क्रियान्वयन का प्रमाण है। कैबिनेट ने हाल ही में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत चार अतिरिक्त सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 30 अगस्त, 2025 को जापान में एक सेमीकंडक्टर सुविधा का प्रधानमंत्री का दौरा और जापानी निवेश प्रतिबद्धताओं का नवीनीकरण, लचीली और विश्वसनीय तकनीकी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए एक साझा रोडमैप को रेखांकित करता है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था इन लाभों को कई गुना बढ़ा देती है। भारत रीयल-टाइम भुगतान में दुनिया में अग्रणी है; एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस की सर्वव्यापकता छोटे व्यवसायों की उत्पादकता बढ़ाती है, और भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम नवाचार को सेवाओं और समाधानों के निर्यात में बदल रहा है। जब डिजिटल रेल कठोर बुनियादी ढाँचे से मिलती है, तो प्रभाव बढ़ता है - कम घर्षण, अधिक औपचारिकता, और निवेश और उपभोग का एक अच्छा चक्र।

भारत के स्कोरबोर्ड में जवाब हैं

आगे का रास्ता आशाजनक है। स्वतंत्र अनुमान (EY) बताते हैं कि 2038 तक, भारत क़य शक्ति समता (PPP) के संदर्भ में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर सकता है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद 34 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होगा। यह प्रगति निरंतर सुधारों, मानव पूंजी और प्रत्येक उद्यम व परिवार के लिए प्रचुर, स्वच्छ, विश्वसनीय ऊर्जा पर आधारित है।

एक महान सभ्यता की परीक्षा उसके कठिन क्षणों में होती है। अतीत में जब भी संदेह किया गया, भारत ने हरित क्रांति, आईटी क्रांति और शिक्षा व उद्यम के माध्यम से खुद को ऊपर उठाने वाले लाखों लोगों के शांत सम्मान के साथ जवाब दिया। आज का समय भी अलग नहीं है। भारत अपनी दृष्टि स्थिर, अपने सुधारों को निरंतर और अपने विकास को तीव्र, लोकतांत्रिक और समावेशी बनाए रखेगा - ताकि लाभ सबसे वंचितों तक पहुँच सके। आलोचकों के लिए, स्कोरबोर्ड ही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, विकसित भारत कोई आकांक्षा नहीं है। यह एक उपलब्धि है - और ये आँकड़े उस बड़ी कहानी का नवीनतम अध्याय मात्र हैं।